P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-9*(Part-1) December 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

साक्षरता को मिशन बनाने की जरूरत

दिनेश प्रताप सिंह
सहायक प्राध्यापक,
शिक्षा संकाय
आई.एम.आर., गाजियाबाद

सारांश

समाज के वंचित तबकों के सशक्तिकरण और उनके जीवन स्तर को सुधारने में साक्षरता अहम भूमिका निभा सकती है। चूंकि भारत भी आज दुनिया के तमाम देशों की तरह 51वां विश्व साक्षरता दिवस मना रहा है, तो इस मौके पर राष्ट्रों की तरक्की में साक्षरता की केंद्रीय भूमिका की तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह वह दिन है, जब हम अपने स्वतंत्रता संघर्ष और महात्मा गॉधी के शब्दों को याद कर सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि अशिक्षा एक अभिशाप और शर्म है, जिसे मुक्ति पाई जानी ही चाहिए। यह वह दिन है, जब हम अपनी स्वतंत्रता के 70 वर्षों की तरक्की पर निगाह डाल सकते हैं।

मुख्य शब्द : सामाजिक–आर्थिक, चुनौतियां, साक्षरता, सार्थक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।

प्रस्तावना

पंडित नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को बड़े ही सार्थक शब्दों में कहा था, 'आम आदमी को आजादी व अवसर मुहैया कराने के लिए और सामाजिक–आर्थिक व राजनीतिक संगठनों के सृजन के लिए, जो देश के हरेक पुरुष व स्त्री को इंसाफ व आनंदपूर्ण जीवन की गारंटी दे' हमें विकास के मार्ग पर कदम बढ़ाने की जरूरत है।

हमने इन वर्षों में जो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी हैं, जो मील के पत्थर गाड़े हैं, उन्हें गर्व से देख सकते हैं। 1947 में देश जब आजाद हुआ था, तब महज 18 प्रतिशत भारतीय लिख–पढ़ सकते थे। आज करीब 74 फीसदी भारतीय साक्षर हैं। 95 प्रतिशत से भी अधिक बच्चे स्कूल जा रहे हैं और 86 फीसदी नौजवान कामकाज के लायक शिक्षित हैं। यह कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। हालांकि, हमें अपनी पुरानी सफलताओं से प्रेरणा लेते हुए भविष्य की ओर अग्रसर होना है।

निस्संदेह, हमें अभी लंबी दूरी तय करनी है। हम इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं कर सकते कि करीब 35 करोड़ युवा व प्रौढ़ शिक्षा की दुनिया से बाहर हैं, और इसके कारण भारत की तरक्की और विकास में वे कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा पा रहे। इसके अलावा करीब 40 प्रतिशत स्कूली बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद भी बुनियादी साक्षरता कौशल से वंचित रह जाते हैं। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, जिससे हमें व्यवस्थित रूप से निपटना है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. समाज के वंचित तबकों के सशक्तीकरण और उनके जीवन स्तर को सुधारने के सुझाव देना।
2. राष्ट्रों की तरक्की में साक्षरता की केंद्रीय भूमिका का अध्ययन।
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा में चयन के सुझाव।
4. मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था का मूल्याकन।

आज के दिन हमें अपनी सामूहिक उपलब्धि का उत्सव मनाने का अवसर दिया है। यह हमारे अथक प्रयासों की प्रेरक कहानी है। अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं ने इस राष्ट्रीय कोशिश में अपना योगदान दिया है। त्रावणकोर और बड़ौदा के बौद्धिक शासकों ने शिक्षा के अवसरों का विस्तार किया था। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हुए वेल्दी फिशर और लौबाह ने 1953 में लखनऊ में लिटरेसी हाउस की स्थापना की थी। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 1959 में ही ग्राम शिक्षण मुहिम जैसे कार्यक्रम चलाए गए थे। लेकिन 1990 के दशक में सरकार के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने इन प्रयासों को जबर्दस्त रफ्तार दी। और इन तमाम प्रयासों को ही इस बात का श्रेय जाता है कि आज हमारी तीन–चौथाई आबादी लिख–पढ़ सकती है।

हालांकि, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चुनौतियां अब भी कम नहीं हैं और वे फौरन ध्यान दिए जाने की मांग भी करती हैं। सरकार मानती है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्यामन (चीन) के ब्रिक्स सम्मेलन में बीते 5 सितंबर को कहा भी है कि ''हमारे विकास संबंधी एजेंडे का आधार 'सबका साथ, सबका विकास' की धारणा है। यानी ''सामूहिक प्रयास'' और समावेशी विकास।'' अगले पांच वर्षों में एक नए भारत को आकार देने में भी देश जुटा हुआ है। वैश्विक रूप से हम जनवरी 2016 के उस संयुक्त राष्ट्र के ''2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट'' प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस वैश्विक एजेंडे में एक 'सार्वभौमिक साक्षर दुनिया' की परिकल्पना की गई है। और इस एजेंडे के एक लक्ष्य को, जो खास तौर से नौजवानों और प्रौढ़ों की साक्षरता पर केंद्रित है, साल 2030 तक हासिल करना है। विद्यार्थियों को पूरी तरह समझना उनकी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियों को जानना, जो ज्ञान और समझदारी लेकर बच्चा स्कूल में आता है। उसका अनुमान लगाकर आगे बढाना होगा। मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था के बाद भी बच्चे कुपोषित है। कौन उत्तरदायी है इसके लिए?

अगर हमें 2030 तक साक्षर दुनिया की लक्ष्य–प्राप्ति की ओर तेजी से बढ़ना है और भारत को यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नौजवान और प्रौढ़ों की एक बड़ी संख्या इस कौशल को प्राप्त कर सके, तो हमें अपनी पुरानी रणनीति की समीक्षा करनी होगी और कौन सी नीति कारगर रही व कौन निरर्थक, यह जानने के बाद देश के भीतर व बाहर के सफल उदाहरणों से सबक सीखना होगा। निस्संदेह, इसे एक सामूहिक प्रयास बनाना पड़ेगा, जिसमें सरकार की भूमिका अग्रणी हो, लेकिन सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्र भी सक्रिय भूमिका निभाएं। इस स्पष्ट सोच के साथ कि शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका नए भारत को आकर दे सकती है, इसे एक सामाजिक मिशन बनाना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा के अग्रणी देशों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षकों की गुणवत्ता से ही आगे चलकर अन्य सभी क्षेत्रों मे गुणवत्ता का स्तर निर्धारित होता है। भारत में इस समय शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक है। यहॉ व्यापारीकरण तेजी से बढ़ा है। और इससे निपटने के प्रयासों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नही है। अध्यापकों की गुणवत्ता में कमी रोकी जानी चाहिये वही पढा सकता है। जिसे नया सीखने में रूचि हो जो अपने अध्यापन में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने को तत्पर रहता है।मौजूदा दौर में हर एक अध्यापक का प्रशिक्षण आधुनिक विधियों से होना चाहिए आज के संचार तकनीकी युग में कैसे पढाये एक अत्यन्त चुनौती प्रश्न बन गया है। सीखने के स्रोतों का विस्तार हुआ है। उनमें बदलाव आता जा रहा है। केन्द्र सरकार ने अपने व्यवस्था में कई सुधार किये है। राज्य सरकार भी व्यवस्था में लग जाये तो निश्चित ही अगले 2 तीन वर्षो में शिक्षा के क्षेत्र में सभी को व्यापक सुधार नजर आने लगेगा। इसके लिए अध्यापको की नियुक्तियों को भलि दी जाये और पाठयक्रम परिवर्तन में तेजी लायी जाए। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था को संभाला जाए, संचार व तकनीकी प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाए लोगो में विश्वास जगाया जाए की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का हर सभंव प्रयास होगा तभी उच्च शिक्षा को सुधारा जाना संभव होगा।

मुझे प्रसिद्ध तेलुगु कवि गुरजाड अप्पाराव की पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसका आशय यह है कि 'हमारे कदमों के नीचे की धरती देश नहीं है, बल्कि जो इस भूमि पर बसे हैं, वे लोग देश होते हैं।' उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता ही किसी देश का चरित्र बताती है। यह समानता है, जो यह तय करती है कि विकास के सुफल का किस तरह वितरण हुआ? हम समावेशी विकास के प्रति समर्पित देश हैं। हम अपने कार्यक्रम इस तरह गढ़ रहे हैं, जिसमें कोई पीछे छूट पाए। ऐसे में, यह स्वाभाविक है कि एक सहभागी जीवंत और अधिक समावेशी लोकतंत्र के निर्माण में साक्षरता पहला जरूरी कदम है।

निष्कर्ष

साक्षरता एक नागरिक को अपने उन अधिकारों के इस्तेमाल में सक्षम बनाती है, जो उसे संविधान से मिले हैं। यह देखा गया है कि गरीबी, शिशु मृत्यु–दर, जनसंख्या वृद्धि, लैंगिक गैर–बराबरी जैसी समस्याओं से शिशु समाज बेहतर तरीके से निपटते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य साक्षरता हमारे देश व समाज के वंचित तबके का सशक्तीकरण और उनके जीवन स्तर को सुधारने में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सार्वभौमिक साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी द्विपक्षीय रणनीति जारी रखनी पड़ेगी। हमें प्री–प्राइमरी शिक्षा और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी पड़ेगी, ताकि हमारे सभी स्नातकों के आवश्यक साक्षरता कौशल हो। दूसरी, उन तमाम को सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा या जिन्हें बीच में किन्हीं वजहों से छोड़ना पड़ा। हमें उन नौजवानों व प्रौढ़ों को भी अवसर देने होंगे, जिन्हें अपनी आजीविका के अवसरों के लिए बुनियादी कौशल हासिल करने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *संपादकीय दैनिक जागरण, दिनांक 10अगस्त 2018*
2. *लाल, रमन बिहारीः भारतीय शिक्षा की समस्याये, आर लाल पब्लिकेशन मेरठ*
3. *पाठक, पी.डी.: भारतीय शिक्षा की समस्याये, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा*
4. *पाल, डा0 राजकुमार : शिक्षा की समस्याये, विवेक पब्लिकेशन दिल्ली*
5. *शर्मा, आर. ए. : शिक्षा और उसका इतिहास, आर लाल पब्लिकेशन मेरठ*